

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION No-155
ANSWERED ON- 21/12/2022

SPENDING ON EDUCATIONAL RESEARCH

*155. DR. ASHOK KUMAR MITTAL:

Will the Minister of Education be pleased to state:

- (a) the number of students graduated from each field as provided and approved by the University Grants Commission (UGC);
- (b) the cumulative spending of all educational institutions in the country for research and development and spending on each field respectively;
- (c) the details of spending of both Government and private institutions in educational research; and
- (d) whether Government plans to promote spending and quality of research and development in the country in the context of higher education?

ANSWER

THE MINISTER OF EDUCATION
(SHRI DHARMENDRA PRADHAN)

- (a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

**STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) to (d) OF RAJYA SABHA
STARRED QUESTION No. 155 FOR REPLY ON 21.12.2022 ASKED BY
DR. ASHOK KUMAR MITTAL, HON'BLE MEMBER OF PARLIAMENT REGARDING
SPENDING ON EDUCATIONAL RESEARCH.**

(a): As per information received from the University Grants Commission (UGC), it does not provide programme wise approval to the Higher Educational Institutions (HEIs). The recognized universities are empowered to offer programmes in various fields leading to award of degrees specified u/s 22(3) of UGC Act, 1956. However, as per All India Survey on Higher Education 2020-21, out-turn / pass-outs at Under Graduate level in Major Disciplines/ subjects is available at Annexure.

(b) to (d): The Government has been putting consistent efforts to promote spending and quality of Research & Development (R&D) in the Country. The Department of Science & Technology (DST) brings out the R&D statistics. The DST has informed that as per the latest available R&D Statistics, December 2020, the national expenditure on research and development measured in terms of Gross Expenditure on Research and Development (GERD) during the years 2015-16 to 2017-18 was ₹.95452.44 crore, ₹.103099.26 crore and ₹.113825.03 crore respectively. It is estimated to be of the order of ₹.123847.71 crore for the year 2018-19. In absolute terms India's GERD has been continuously increasing over the years and has been increased by three times in last 10 years. The National expenditure on R&D in the Higher Education Sector has also increased from ₹.5512.83 crore during 2014-15 to an estimated ₹.8797.08 crore during 2018-19, thus marking an increase of 59.57%.

The Department of Higher Education and other Ministries of the Government of India like the DST, Department of Biotechnology, Council of Scientific & Industrial Research, Indian Council of Agricultural Research, Indian Council of Medical Research are implementing various schemes for promoting research and development in the Higher Educational Institutions (HEIs). Further, the HEIs are also being encouraged to collaborate with the private sector, Alumni Associations, startups and entrepreneurship to augment the research efforts.

ANNEXURE AS REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION No. 155 FOR REPLY ON 21.12.2022 ASKED BY DR. ASHOK KUMAR MITTAL, HON'BLE MEMBER OF PARLIAMENT REGARDING SPENDING ON EDUCATIONAL RESEARCH.

2020-21 Out-turn/Pass-Out at Under Graduate Level in Major Disciplines/ Subjects
(Based on Actual Response)

Discipline		Male	Female	Total
Arts		908169	1135968	2044137
Science		504531	604498	1109029
Commerce		496879	523734	1020613
Engineering & Technology	Computer Engineering	121756	83874	205630
	Mechanical Engineering	153508	9439	162947
	Electronics Engineering	73672	59779	133451
	Civil Engineering	87954	26364	114318
	Electrical Engineering	59026	24576	83602
	Information Technology	28191	14276	42467
	Other Engineering & Technology	26855	12746	39601
	Architecture	6634	7705	14339
	Chemical Engineering	8870	2901	11771
	Agriculture Engineering	3087	1427	4514
	Aeronautical Engineering	3041	973	4014
	Food Technology	1782	1538	3320
	Metallurgical Engineering	1500	456	1956
	Mining Engineering	1649	36	1685
	Instrumentation Engineering	1002	639	1641
	Marine Engineering	1147	99	1246
	Dairy Technology	538	263	801
	Planning	270	192	462
	Automotive Studies	328	9	337
	Urban Planning	12	6	18
Education		230318	425157	655475
Medical Science	Nursing	15844	63083	78927
	Pharmacy	31590	24386	55976
	General Medicine	12899	13983	26882
	Medical Science	10148	15451	25599
	Dentistry	4410	13483	17893
	Physiotherapy	3488	8676	12164
	Ayurveda	3946	6256	10202
	Homeopathy	2657	4912	7569
	Other Medical Science	1943	2517	4460
	Indian Medicine	696	1132	1828
	Unani	610	854	1464
	Bio-Technology	494	873	1367
	Ophthalmology	484	794	1278
	Medical Management	683	399	1082
	Occupational Therapy	269	648	917
	Microbiology	250	667	917
	Bio-Chemistry	215	417	632
	Pathology	158	416	574

	General Surgery	81	128	209
	Radiology	103	91	194
	Physiology	54	78	132
	ENT	55	48	103
	Anatomy	46	52	98
	Public Health	54	42	96
	Gynaecology	50	46	96
	Pediatrics	50	46	96
	Forensic Medicine/ Toxicology	32	48	80
	Lab Medicine	44	34	78
	Anesthesiology	21	20	41
	Nephrology	10	14	24
	Nuclear Medicine	10	9	19
	Cardiology	4	5	9
	Neurology	2	3	5
	Radiotherapy	2	2	4
Social Science		107678	114456	222134
IT & Computer		117985	92512	210497
Management		108622	72064	180686
Law		61125	30103	91228
Indian Language		22685	43553	66238
Agriculture		38212	15387	53599
Foreign Language		14508	19475	33983
Library & Information Science		10377	10646	21023
Physical Education		13926	6481	20407
Oriental Learning		10910	9290	20200
Home Science		1729	14629	16358
Fine Arts		4620	5322	9942
Journalism & Mass Communication		4209	4091	8300
Area Studies		3108	4711	7819
Social Work		2982	3358	6340
Design		1776	4506	6282
Paramedical Science		2955	2845	5800
Fashion Technology		901	3469	4370
Hospitality and Tourism		3299	879	4178
Veterinary & Animal Sciences		2437	1413	3850
Linguistics		858	1976	2834
Fisheries Science		756	750	1506
Cultural Studies		461	889	1350
Religious Studies		647	646	1293
Marine Science / Oceanography		346	24	370
Defence Studies		124	166	290
Women Studies		0	276	276
Gandhian Studies		100	11	111
Criminology & Forensic Science		32	67	99
Footwear Design		60	34	94
All India		3349549	3560297	6909846

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-155
उत्तर देने की तारीख-21/12/2022

शैक्षिक अनुसंधान पर खर्च

*155 डा. अशोक कुमार मित्तल:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रदत्त और अनुमोदित प्रत्येक क्षेत्र से स्नातक हुए छात्रों की संख्या कितनी है;
- (ख) देश में सभी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अनुसंधान और विकास के लिए कुल कितना व्यय किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र पर क्रमशः कितना व्यय किया गया है;
- (ग) शैक्षिक अनुसंधान में सरकारी और निजी संस्थानों द्वारा किए जा रहे व्यय का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या उच्च शिक्षा के संदर्भ में सरकार की देश में अनुसंधान और विकास पर व्यय और गुणवत्ता में बढ़ोतरी करने की योजना है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

‘शैक्षिक अनुसंधान पर खर्च’ के संबंध में माननीय संसद सदस्य डा. अशोक कुमार मित्तल द्वारा दिनांक 21.12.2022 को उत्तर के लिए पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 155 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, यह उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को कार्यक्रम-वार अनुमोदन प्रदान नहीं करता है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम प्रदान करने का अधिकार है जिनमें यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22(3) के तहत विनिर्दिष्ट डिग्रियां प्रदान की जाती हैं। तथापि, अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, प्रमुख शिक्षा शाखाओं/विषयों में अवर स्नातक स्तर पर उत्तीर्ण छात्रों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) से (घ): सरकार देश में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) पर व्यय और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) अनुसंधान एवं विकास संबंधी आंकड़े प्रकाशित करता है। डीएसटी ने सूचित किया है कि नवीनतम उपलब्ध आरएंडडी आंकड़े, दिसंबर 2020 के अनुसार, वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान अनुसंधान और विकास पर सकल व्यय (जीईआरडी) के संदर्भ में अनुसंधान और विकास पर परिकलित राष्ट्रीय व्यय क्रमशः ₹95452.44 करोड़, ₹103099.26 करोड़ और ₹113825.03 करोड़ था। वर्ष 2018-19 के लिए इस राशि के ₹123847.71 करोड़ होने का अनुमान है। वस्तुतः, भारत का जीईआरडी पिछले वर्षों से लगातार बढ़ रहा है और पिछले 10 वर्षों में तीन गुना बढ़ गया है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पर 2014-15 के दौरान हुआ राष्ट्रीय व्यय ₹5512.83 करोड़ से बढ़कर 2018-19 के दौरान अनुमानित ₹8797.08 करोड़ हो गया है, जो 59.57% की वृद्धि दर्शाता है।

उच्चतर शिक्षा विभाग और भारत सरकार के अन्य मंत्रालय जैसे डीएसटी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रहे हैं। इसके अलावा, अनुसंधान प्रयासों को बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को निजी क्षेत्र, पूर्व छात्र संघों, स्टार्टअप्स और उद्यमिता के साथ सहयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

‘शैक्षिक अनुसंधान पर खर्च’ के संबंध में माननीय संसद सदस्य डा. अशोक कुमार मित्तल द्वारा दिनांक 21.12.2022 को उत्तर के लिए पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 155 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

2020-21, प्रमुख शिक्षा शाखाओं / विषयों में अवर स्नातक स्तर पर उत्तीर्ण छात्र
(वास्तविक प्रतिक्रिया के आधार पर)

विषय		महिला	पुरुष	कुल
कला		908169	1135968	2044137
विज्ञान		504531	604498	1109029
कॉमर्स		496879	523734	1020613
इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी	कंप्यूटर इंजीनियरिंग	121756	83874	205630
	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	153508	9439	162947
	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	73672	59779	133451
	सिविल इंजीनियरिंग	87954	26364	114318
	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	59026	24576	83602
	सूचना प्रौद्योगिकी	28191	14276	42467
	अन्य इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी	26855	12746	39601
	आर्किटेक्चर	6634	7705	14339
	केमिकल इंजीनियरिंग	8870	2901	11771
	कृषि इंजीनियरिंग	3087	1427	4514
	एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग	3041	973	4014
	खाद्य प्रौद्योगिकी	1782	1538	3320
	धातुकर्म इंजीनियरिंग	1500	456	1956
	खनन अभियांत्रिकी	1649	36	1685
	इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग	1002	639	1641
	मरीन इंजीनियरिंग	1147	99	1246
	डेयरी प्रौद्योगिकी	538	263	801
	योजना	270	192	462
	ऑटोमोटिव स्टडीज	328	9	337
	शहरी आयोजना	12	6	18
	शिक्षा		230318	425157
चिकित्सा विज्ञान	नर्सिंग	15844	63083	78927
	फार्मसी	31590	24386	55976
	सामान्य दवा	12899	13983	26882
	चिकित्सा विज्ञान	10148	15451	25599
	दंत चिकित्सा	4410	13483	17893
	फिजियोथेरेपी	3488	8676	12164
	आयुर्वेद	3946	6256	10202
	होम्योपैथी	2657	4912	7569
	अन्य चिकित्सा विज्ञान	1943	2517	4460
	भारतीय मेडिसिन	696	1132	1828
	यूनानी	610	854	1464
	जैव-प्रौद्योगिकी	494	873	1367
	नेत्र विज्ञान	484	794	1278
	चिकित्सा प्रबंधन	683	399	1082
	ऑक्यूपेशनल थेरेपी	269	648	917
	माइक्रोबायोलॉजी	250	667	917
	जैव रसायन विज्ञान	215	417	632
	पैथोलॉजी	158	416	574
	सामान्य शल्य चिकित्सा	81	128	209
	रेडियोलोजी	103	91	194
	फिजियोलॉजी	54	78	132
	ईएनटी	55	48	103
	एनोटॉमी	46	52	98

	जन स्वास्थ्य	54	42	96
	स्त्री रोग	50	46	96
	शिशु रोग	50	46	96
	फॉरेंसिक मेडिसिन / टॉक्सिकोलॉजी	32	48	80
	लैब मेडिसिन	44	34	78
	एनेस्थेसियोलॉजी	21	20	41
	नेफ्रोलॉजी	10	14	24
	न्यूक्लियर मेडिसिन	10	9	19
	कार्डियलजी	4	5	9
	न्यूरोलॉजी	2	3	5
	रेडियोथेरेपी	2	2	4
सामाजिक विज्ञान		107678	114456	222134
आईटी एंड कंप्यूटर		117985	92512	210497
प्रबंधन		108622	72064	180686
विधि		61125	30103	91228
भारतीय भाषा		22685	43553	66238
कृषि		38212	15387	53599
विदेशी भाषा		14508	19475	33983
पुस्तकालय और सूचना विज्ञान		10377	10646	21023
शारीरिक शिक्षा		13926	6481	20407
ओरिएंटल लर्निंग		10910	9290	20200
गृह विज्ञान		1729	14629	16358
ललित कला		4620	5322	9942
पत्रकारिता और जनसंचार		4209	4091	8300
एरिया स्टडीज़		3108	4711	7819
सामाजिक कार्य		2982	3358	6340
डिज़ाइन		1776	4506	6282
पैरामेडिकल साइंस		2955	2845	5800
फैशन प्रौद्योगिकी		901	3469	4370
आतिथ्य और पर्यटन		3299	879	4178
पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान		2437	1413	3850
भाषा विज्ञान		858	1976	2834
मत्स्य विज्ञान		756	750	1506
सांस्कृतिक अध्ययन		461	889	1350
धार्मिक अध्ययन		647	646	1293
समुद्री विज्ञान / समुद्र विज्ञान		346	24	370
रक्षा अध्ययन		124	166	290
महिला अध्ययन		0	276	276
गांधीवादी अध्ययन		100	11	111
अपराध विज्ञान और फॉरेंसिक विज्ञान		32	67	99
फुटबल डिज़ाइन		60	34	94
अखिल भारतीय		3349549	3560297	6909846

डा. अशोक कुमार मित्तल : महोदय, हम सबके महान गुरु महाराज श्री गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से कल ही गुरु नगरी अमृतसर में स्थित गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को भारत सरकार के NAAC ने चार में से 3.85, यानी 96 परसेंट से ज्यादा अंक देकर भारत की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी घोषित किया है।

श्री उपसभापति : आप सवाल पूछिए।

डा. अशोक कुमार मित्तल : सर, मैं सवाल पर ही आ रहा हूँ। मैं इसके लिए सबसे पहले पंजाब की जनता को, पंजाब के मुख्य मंत्री को, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और स्टाफ को बधाई देते हुए इस सदन से निवेदन करूँगा कि वह भी मेरे साथ इसमें शामिल हो, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव महाराज जी के नाम से स्थापित है।

श्री उपसभापति : आप सवाल पूछिए।

डा. अशोक कुमार मित्तल : मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या वे ऐसी हाई रैंक यूनिवर्सिटी को कोई स्पेशल पैकेज देने जा रहे हैं या कोई रिसर्च बेस्ड इन्सैटिव स्कीम देने जा रहे हैं?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : उपसभापति महोदय, आदरणीय सदस्य ने उच्च शिक्षण संस्थान में रिसर्च ग्रांट के बारे में मूल प्रश्न पूछा था। उनको एक संपूर्ण विवरण दिया गया है। अभी उन्होंने स्पेसिफिक पूछा है। सर, भारत सरकार द्वारा चलने वाले उच्च शिक्षण संस्थान एवं राज्य सरकारों द्वारा चलने वाले गुणात्मक उच्च शिक्षण संस्थानों को रिसर्च ग्रांट दी जाती है। अगर हम वर्ष 2018-19 तक का आंकड़ा आपके सामने रखें तो भारत सरकार 1 लाख, 23 हजार, 847 करोड़ अनुदान राशि देती है। उन्होंने अभी स्पेसिफिक प्रश्न पूछा कि क्या NAAC मान्यता के बाद ग्रांट दी जाती है। उपसभापति महोदय, ऐसे NAAC से ग्रांट देने की कोई व्यवस्था नहीं है। NAAC अपने आप में एक बड़ा ऑटोनॉमस इन्डोर्समेंट है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो अनुदान जाती है, वह सारे प्रकार के इंस्टीट्यूशंस में जाती है, उनकी विशेषज्ञता के ऊपर जाती है। NAAC एक अलग प्रकार का पैमाना है।

डा. अशोक कुमार मित्तल : महोदय, आज विश्व में टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग को ऑथेंटिक माना जाता है, जो कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से बनायी गई है। भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी टाइम्स के दो सौ के अंतर्गत नहीं आती है। भारत सरकार ने भारतीय इंस्टीट्यूशंस के लिए NARF रैंकिंग शुरू की, जिसकी क्रेडिबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है। मैं इसके लिए सबसे पहले भारत सरकार को बधाई देना चाहूँगा।

श्री उपसभापति : प्लीज़, आप सवाल पूछें।

डा. अशोक कुमार मित्तल : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या हम भारत में भारत द्वारा कोई इंटरनेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ला रहे हैं, ताकि भारत विश्वगुरु बनने की तरफ आगे बढ़ सके, जो प्रधान मंत्री जी का भी एक सपना है?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : उपसभापति महोदय, आदरणीय सदस्य ने टाइम्स और क्यू.एस. रैंकिंग के बारे में उल्लेख किया है। यह एक प्रकार से वैश्विक स्तर के निजी संस्थान द्वारा चलने वाले मानक की व्यवस्था है। भारत के कई इंस्टीट्यूशंस उसको यूज करते हैं, उस रैंकिंग मेथोडोलॉजी को अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर नापते हैं, आंकते हैं और वे उसमें कहां खड़े होते हैं, यह देखते हैं। मैं आपको विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि इतने दशकों के बाद भी भारत की कोई निजस्व रैंकिंग व्यवस्था -- एक्क्रेडिटेशन हो गया था, लेकिन रैंकिंग व्यवस्था नहीं थी। मोदी जी की सरकार ने भारत की निजस्व रैंकिंग व्यवस्था को खड़ा किया है, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, वह NIRF है। आज भारत में लगभग 1,100 यूनिवर्सिटीज़ और यूनिवर्सिटी स्तर के इंस्टीट्यूशंस, जो स्टेट एक्ट में हैं, सेंट्रल एक्ट में हैं और डीमंड यूनिवर्सिटीज़ के रूप में हैं, उसके अलावा लगभग 50 हजार कॉलेजेज़ हैं, इन सबकी रैंकिंग होनी चाहिए, यह इसी सरकार की पहल है। धीरे-धीरे उसकी मर्यादा बढ़ रही है। हमें कॉम्प्लेक्सिटी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह शुरुआत है। अब चंद दिनों में विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमी भारत की NIRF को लेंगे, उसमें भारत की सभी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस आएंगे। भारत का मानक वैश्विक मानक की ओर बढ़ रहा है, हमारे पास यह आत्मविश्वास है और देश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।

श्री कामाख्या प्रसाद तासा : महोदय, मंत्री जी ने एक विस्तृत उत्तर दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा...

श्री उपसभापति : तासा जी, आप आगे आकर माइक में बोलिए। पीछे की पंक्तियों पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण शायद माइक काम नहीं कर रहे हैं।

श्री कामाख्या प्रसाद तासा : उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट ने 2014-15 में 59.57 परसेंट बढ़ोतरी की है, इसके लिए मैं मोदी जी की गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आर.एंड डी. में कौन-कौन से क्षेत्रों में प्राइयोरिटी के बेसिस पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अनुदान देती है?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या शिक्षा विभाग के द्वारा आर.एंड डी. की स्पेंडिंग बढ़ी है, यह बात सही है। वर्ष 2014-15 में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आर.एंड डी. की स्पेंडिंग 5,512.83 करोड़ रुपये थी, जो आज लगभग 60 परसेंट ग्रोथ के साथ 8,797.08 करोड़ रुपये है। क्या यह पर्याप्त है? सर, मैं विनम्रता से यह कहता हूं कि शायद यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, यह उच्च शिक्षा की स्पेंडिंग है, लेकिन भारत की व्यवस्था में सिर्फ उच्च शिक्षा आर.एंड डी. पर खर्चा नहीं करती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करता है, बायो-टेक्नोलॉजी करता है, एटॉमिक एनर्जी करता है, अर्थसाइंस करता है, डिपार्टमेंट

ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन करता है और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री भी अपने आप में आर.एंड डी. के लिए स्पेंडिंग करती है, जिसका आपने समूचा विवरण दिया कि लगभग 1 लाख, 23 हजार करोड़ रुपये होता है। भारत की जो एस्पिरेशन है, क्या उस दिशा में यह पर्याप्त है? मैं कहना चाहूंगा कि नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) की कल्पना की गई है, जिसमें वैज्ञानिक रिसर्च, सामाजिक क्षेत्र की रिसर्च और अर्बन एरियाज़ का एक कन्सेन्सस बनाया जा रहा है। एक एस्पिरेशनल सोसाइटी के नाते भारत की जो आवश्यकता है, जिससे धीरे-धीरे भारत में उद्यमिता बढ़ रही है, स्टार्टअप्स की नई रचना बन रही है, इन दिनों यूनिवर्सिटी खूब तेजी से बढ़ा है, तो उस दिशा में अकादमियां, इंडस्ट्रीज़ और पॉलिसी मेकिंग की हम एक कॉम्प्रेहेन्सिव स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, एनआरएफ उस दिशा में एक कदम है, आने वाले दिनों में सबके प्रयास से - राज्य सरकार अपना खर्चा करे, हम इंडस्ट्री को पॉलिसी इनेबल करे, जिससे वह भी खर्चा कर पाए - इन सबको मिलाकर भारत की वैश्विक आवश्यकता में हमारी मैनपावर जहां काम करने जाएगी, उस दिशा में आर. एंड डी. की स्पेंडिंग बढ़ाई जाएगी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. L. Hanumanthaiah; not present. Shri A.A. Rahim.

SHRI A.A. RAHIM: Thank you, Sir, for this opportunity. In 1964, the National Education Commission, popularly known as Kothari Commission, was set up. The Commission submitted its report in 1966, that is, 56 years ago. The report recommended that spending on education should be at least 6 per cent of the GDP.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put your question, please.

SHRI A.A. RAHIM: My question is: What is the current spending on education as percentage of GDP? And, why, even today, we cannot match the target set in 1966?

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Sir, this is altogether a separate question. The primary question is about R&D spending and the hon. Member is asking about overall spending on education. The information that I have right now may not be the exact one. I can share with him more accurate information. But if I can remember correctly, today, putting together, we have the spending from the different Ministries of the Government of India, the State Governments and also by some of the industries and some of the philanthropists, if you see, in the recent past, the IITs are getting older; the alumni are now well created; so many multi-billionaires are there. They have now started spending in the education sector. ...*(Interruptions)*...

SHRI A.A. RAHIM: What is the percentage of GDP? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: If you are asking the question, you must have at least this much of patience to get my answer. I am coming to your point. This question is not related to education spending. I am coming to that. Please have patience.

I can say, roughly, that putting together all these sources, today's spending is 4.64 per cent of the GDP. Recently, for the first time, after a long gap, in the 2022-23 Budget, our Prime Minister, Modi ji, has allocated more than one lakh crore rupees from the Central Government treasury. This is the information I have today.

श्रीमती रंजीत रंजन : माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ऐसे तो हमारा देश शिक्षा के मामले में, विश्वविद्यालय में पूरे विश्व में तीसरे नम्बर पर है, लेकिन आज भी बहुत सारे महाविद्यालय ऐसे हैं, जहाँ पर बुनियादी सुविधाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं यह पूछना चाहती हूँ कि छोटे जिलों के जो गरीब प्रदेशों के विश्वविद्यालय हैं, उन संस्थाओं में प्रयोगशालाओं को न्यास रूप देने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की क्या आप कोई जानकारी देंगे? क्या आपने इस संबंध में कोई प्लानिंग की है? एक तरफ तो विकास और लाभ की बात की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं ही नहीं हैं, क्या उस पर सरकार का कोई पुख्ता प्लान है?

श्री उपसभापति : धन्यवाद, रंजीत रंजन जी। माननीय मंत्री जी।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : उपसभापति महोदय, आदरणीय सदस्या का प्रश्न वाजिब है, लेकिन शिक्षा कन्करेंट लिस्ट में है। राज्य के द्वारा चलने वाले उच्च शिक्षण संस्थान हों या स्कूल शिक्षा की व्यवस्था हो, इसकी प्राइमरी स्पेंडिंग राज्य सरकार की है। भारत सरकार उच्च शिक्षा में, अगर कॉलेज के बारे में कहें, उच्च शिक्षा में राज्य सरकार को मदद करने के लिए RUSA जैसी स्कीम के अंतर्गत मदद करती है। यह बात सही है कि आज जो 50 हजार कॉलेज देश में हैं, जो ज्यादातर जिला स्तर पर हैं, सब-डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हैं और उनसे नीचे की इकाई के स्तर पर हैं, उनकी इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता जो है, वह पूरी नहीं हुई है, लेकिन प्राइमरिली, यह राज्य की समझ और राज्य के बजट के आधार पर होता है। मैं बहुत आभारी रहूंगा, मैं उनकी राजनितिक ऊंचाई को जानता हूँ, अगर वे उस ऊंचाई को यूज़ करके, अपने राज्य, जहाँ से वे आती हैं, वहाँ इसको परस्यू करें। आज मैं दुख के साथ कहता हूँ कि बिहार की स्पेंडिंग on higher education is one of the minimal in the country. अगर मैं उनके साथ रहूंगा ...**(व्यवधान)**... यह एक कलेक्टिव विषय है, आदरणीय सदस्या भारत सरकार से जो अपेक्षा रखेंगी, उसे हम पूरा करेंगे, लेकिन प्राइमरिली बिहार राज्य सरकार अगर उसमें जिम्मेवारी लेगी, तो हम उनके साथ रहेंगे। वे थोड़ा वहाँ भी परस्यू करें, तो अच्छा रहेगा।

श्री उपसभापति : क्वेश्चन नम्बर 156.